

सत्त का सबसे बड़ा मित्र समर्थ है। उसका सबसे बड़ा शत्रु पूर्वाग्रह है और उसका सहायी साथी विनमता है - वाल्स कैलब कार्लन

आलोचनाओं के केंद्र

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अर्थनीति एवं समाज अर्थव्यवस्था के आलोचकों को बिना नाम लिपे बिना तहशार और चिन्त के साथ जवाब दिया है। वह यकीनन अपेक्षित था। हालांकि ज़्यादातर आलोचनाओं के केंद्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली रहे हैं। किंतु अर्थनीति में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए आलोचनाओं में मोदी का नाम हो या नहीं निशाने पर वे भी हैं। और नोटबंदी और को अकेले उनके दिमाग की उपज ही माना जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ़ कॉर्पोरेट सेक्टोर्स ऑफ़इंडिया के स्वर्ण जयंती समारोह ने उन्हें इसका अवसर भी उपलब्ध करा दिया। उन्होंने एक और आलोचनाओं को यह कहकर दरकिनार किया कि अर्थव्यवस्था के आधार मजबूत हैं तो दूसरी ओर देश को आसरा भी किया कि सरकार वित्तीय स्थिरता कायम रखकर निवेश बढ़ाने का कदम उठाती रहेगी, जिससे आने वाले समय में देश विकास की राई लाने में होगा। ऐसा नहीं है कि आलोचक मोदी के तर्कों और तबरे से संतुष्ट होकर चुप हो जाएंगे। कुछ की आलोचना अभी भी जारी है। मोदी को भी इसका आभास था कि उनके द्वारा विस्तार से आलोचनाओं का जवाब देने के बावजूद वे संतुष्ट नहीं होने वाले। कारण, अर्थव्यवस्था की आलोचना में आर्थिक से नहीं ज़्यादा राजनीतिक नज़रिये की भूमिका है। वस्तुतः वे अपनी पाटी साबित, समर्थकों एवं उन लोगों के लिए बोल रहे थे, जो ऐसी आलोचनाओं के आधार पर यह न मान लें कि अर्थव्यवस्था की स्थिति वाकई चिंताजनक है। कह सकते हैं कि इस वर्ग को उन्होंने एक साझा इतने ज़्यादा आंकड़े एवं तर्क दिए हैं, जिससे यह आलोचनाओं का मुकाबला कर सकते हैं। जीएसटी में असह्यक बदलाव का उनका आश्वासन स्वागतयोग्य है। वैसे भी मोदी ने जो कहा उसमें गलत नहीं है। अलग-अलग क्षेत्रों में पिछले सदी के कार्ये और निवेशों की तुलना करके उन्होंने यह फलकन की कवायद की कि आलोचना करने वाले इन सारे तर्कों को नजरअंदाज कर रहे हैं। सरकार लगातार तेज गति से बदल रहा उछा है। इतने सुधारों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं और प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। बहरहाल, प्रधानमंत्री ने जो भी आंकड़े रखे और तर्क दिए वो उनका दावा था, लेकिन देश में यदि विकास और महंगाई को लेकर चिंता की स्थिति बनी है तो उसे दूर किया जाना चाहिए।

एकमात्र चेहरा अखिलेश

समाजवादी पार्टी के अगार में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को दूसरी बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने से शायद ही किसी को ताज्जुब हुआ होगा। इस साल जनवरी में मुलायम सिंह को अपदस्थ करके जब उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, उसी समय सुनिश्चित हो गया था कि अब समाजवादी पार्टी का एकमात्र चेहरा अखिलेश हैं और परिवर्ध में भी रहेंगे। इसीलिए उनका दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना किसी खसबा के पहले पेज की खबर नहीं बन पाई। किन्तु इस अधिवेशन का महत्वपूर्ण पहलू पार्टी संविधान में संशोधन किया जाना है, जिसके तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को तीन साल से बढ़कर पांच साल किया जायेगा। इस बदलाव के बाद पार्टी में उनका नियंत्रण पूरी तरह स्थापित हो जाएगा। यह अखिलेश की राजनीतिक दूरदर्शिता है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब 2019 का लोक सभा और 2022 का विधान सभा चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ेंगे और आएंगे। समाजवादी पार्टी का सर्वेसर्वा बनने के बाद लोगों को अखिलेश भी उनसे ज़्यादा हो गई है। इसीलिएउनकी चुनौतियां भी कम नहीं हैं। प्रदेश में भाजपा के विकल्प के तौर पर अपनी पार्टी को खड़ी करना उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। सवाल यह है कि क्या इसके लिए वह पार्टी के संगठनात्मक ढांचे का पूरी तरह स्फुटपर करने का जोखिम उठाना चाहेंगे। सवाल यह भी है कि मुलायम सिंह की परंपरावादी जातिवादी राजनीति से अलग हटकर क्या आधुनिक और नवीन मान्यने में प्रगतिशील राजनीति की शुरुआत करेंगे, जिसमें जाति और अपभवी तत्वों के लिएकोई स्थान नहीं रहेगा। इसमें तो यथार्थ नहीं कि देश और प्रदेश की राजनीति में उनकी छवि एक स्वच्छ और बेदना नती है। अलसता, युवाओं के बीच वे लोकप्रिय भी हैं। यह भी देखा जा भी बाकी है कि वह संसदन में युवाओं को बिना आगे बढ़ाते हैं। ज़्यादा सब नहीं हुए जब उन्होंने प्रदेश के कुछ अपराधियों को पचास से दूर रखने में कामयाबी पाई थी। प्रदेश में वह सबसे खड़ी विपक्षी पार्टी के नेता हैं। आगे वाले दिनों में स्पष्ट होगा कि प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा से लड़ने के लिए विपक्षी दलों की एकता का कोई प्रयास करने है या नहीं। इनके नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी को मारवाती की बसपा के साथ यह जगह नहीं मिलेगी जो शुरुआत हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उम्मीद है उनके युवा नेतृत्व में समाजवादी पार्टी प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दिखाएगी।

सत्संग

आत्म-सम्मोहन

आप ध्यान कर रहे हैं, उसमें और आगे-हिप्पिसिस में, आत्म-सम्मोहन में क्या कर रहे हैं? वही फर्क है, जो नींद और ध्यान में है। इस बात को भी समझ लेना उचित है। नींद है प्राकृतिक रूप से आई हुई, और आत्म-सम्मोहन भी निद्रा है प्रयत्न से लाई हुई। इतना ही फर्क है। हिप्पिसिस में-हिप्पिस का मतलब जो नींद होता है-हिप्पिसिस का मतलब हो होता है तंदा, उसका मतलब होता है सम्मोहन। एक तो ऐसी नींद है जो अपने आप आ जाती है, और एक ऐसी नींद है जो कर्तवीय करनी पड़ती है, लाती पड़ती है। किसी को नींद न आती हो तो फिर उसको लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तब एक आसामी अगर लेटरक सोचे कि नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, तो सो रहा हूँ, तो यह जब उसके प्रार्थनों में घुम जाए, घुम जाए, घुम जाए, उसका मन पकड़ ले कि मैं सो रहा हूँ, नींद आ रही है, तो शरीर उसी तरह का व्यवहार करना शुरू कर देता। क्योंकि शरीर कहता कि नींद आ रही है तो अब स्थिति हो जाओ। नींद आ रही है तो। थोड़े करोंगे। आप स्थिति हो जाओ। नींद आ रही है तो। मैं मन करेगा कि अब चुप हो जाऊँ। नींद आ रही है, उसका तात्पर्य ध्यान कर दिया जाए भीतर तो शरीर उसी व्यवहार करने लगेगा। शरीर को इससे कोई मतलब नहीं है। शरीर तो बहुत आकारहीन है। अगर आपको रोग प्यारह बने भूत लाती हैं, रोग आप खाना छोड़ देते हैं प्यारह बने और आज नहीं बने अभी नहीं भर पाए हैं और घड़ी रात में हो प्यारह बने र क आई है और आंखें सूज के आठ हो बने हैं और आप देखें और देखें कि प्यारह बने हैं, एकदम परे कहेंगे। घुछ लाई आई। अभी प्यारह बने नहीं हैं, अभी नींद नहीं है बनेने में। लेकिन घड़ी कहा है कि प्यारह बने गए हैं, परे एकदम से खबर कर देना कि भूछ बने गए हैं क्योंकि एक तो यौनिक व्यवस्था है। प्यारह बने रोग प्यारह लाती हैं। तो प्यारह बने गए तो प्यारह लाते हैं, परे खबर कर देते हैं, परे बिनाखल खबर कर देना कि प्यारह लाई है। रोग रात बरबस आए आते हैं और आप दस ही बने हैं और घड़ी ने बारह के घंटे बजा दिए, घड़ी के घंटे देखकर आप फौरन पार्टी की तंदा उठाने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि शरीर कहता कि बारह बने गए, अब सो जाना चाहिए। शरीर बहुत आकारहीन है, और जितना स्वस्थ शरीर होता, उतना ज़्यादा आकारहीन होगा। स्वस्थ शरीर का मतलब ही यह होता है, आकारहीन शरीर।

“लाल-जेहादी आतंक” का मुकाबला

आरएसएस-भाजपा इस मुहिम के जरिए पूरे देश को समझाने की कोशिशों में लगे हुए हैं कि उनके कार्यकर्ता केरल और वामपंथ की महत्वपूर्ण उपस्थिति वाली दूसरी जगहों पर भी लगातार कम्युनिस्टों की “लाल हिंसा” के शिकार हो रहे हैं, कि वामपंथी प्रभाव वाले इलाकों में उनके प्रभाव का विस्तार रोकने के लिए उनके खिलाफ व्यवस्थित रूप से हिंसा का प्रयोग किया जा रहा है। बेशक, यह प्रचार कोई नया नहीं है। फिर भी केरल के पिछले विधान सभा चुनाव में एलडीएफ की जीत के बाद से इस अभियान को बहुत तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में वह कई बार अल्पसंख्यक समूहों और जमीनी स्तर पर उनके पक्ष में खड़े होने वाले कम्युनिस्टों।

सतीश पेड्डीकार

जनता के इस बढ़ते असंतोष को मोदी सरकार और भाजपा के राजनीतिक विरोध की आवाज बनने से रोकने के लिए वामपंथ को कमजोर करने की कोशिश करना खास तौर पर जरूरी है। अब, जब ज़्यादातर विपक्षी पार्टियों को या तो सत्ता पक्ष द्वारा साधा जा चुका है, या सीबीआई केसों समेत तरह-तरह के मामलों में उलझाया जा चुका है, उन्हें वामपंथ से ही खास खतरा है, जिसकी आवाज राजनीतिक-वैचारिक रूप से प्रखर भी है, और आम जनता के बीच उसकी अनुगुं भी है। पीपुल और केरल की उसकी एलडीएफ सरकार, आरएसएस-भाजपा के खास निशाने पर हैं। केरल में कथित “लाल-जेहादी आतंक” का मुकाबला करने के नाम पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा छेड़ी गई “जन सुरक्षा यात्रा” इसी का एक और संस्करण है। इसे बढ़ावाचालि यात्रा में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।

चार-चार रण्यों के भाजपायी मुख्यमंत्रियों और आधे दर्जन से ज़्यादा केंद्रीय मंत्रियों को इस मुहिम में केरल में उतारा जाना, इसी की ओर इशारा करता है। दूसरी ओर, इस मुहिम को देश भर में फैलाने की कोशिश में भाजपा अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं को सभी रण्यों की राजधानियों में सीपीएम कार्यालयों पर प्रदर्शन करने की और राजधानी दिल्ली में सीपीएम केंद्रीय कार्यालय पर इस यात्रा के दौरान दस दिन लगातार प्रदर्शन करने का अभ्युत्प्रेरित किया है।

आरएसएस-भाजपा इस मुहिम के जरिए पूरे देश को समझाने की कोशिशों में लगे हुए हैं कि उनके कार्यकर्ता केरल और वामपंथ की महत्वपूर्ण उपस्थिति वाली दूसरी जगहों पर भी लगातार कम्युनिस्टों की “लाल हिंसा” के शिकार हो रहे हैं, कि वामपंथी प्रभाव वाले इलाकों में उनके प्रभाव का विस्तार रोकने के लिए उनके खिलाफ व्यवस्थित रूप से हिंसा का प्रयोग किया जा रहा है। बेशक, यह प्रचार कोई नया नहीं है। फिर भी केरल के पिछले विधान सभा चुनाव में एलडीएफ की जीत के बाद से इस अभियान को बहुत तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में वह कई बार अल्पसंख्यक समूहों और जमीनी स्तर पर उनके पक्ष में खड़े होने वाले कम्युनिस्टों, जो राजनीतिक-विचारधारात्मक रूप से उसके सबसे कट्टरविरोधी हैं, से हिंसक झड़पों में भी शामिल रहा है।

2014 के आम चुनाव में देश भर में अपनी सफलता के बाद भी भाजपा केरल में अपना खाला न खोल पाए के बावजूद अपने मत फाँटने में ध्यान देने लायक बढ़ोतरी करने में और पहली बार एक अंद की देहली लांघने में कामयाब रही थी। उसके बाद से केंद्र में मोदी सरकार की मौजूदगी से और उसाहित आरएसएस-भाजपा ने पिछले विधानसभायी चुनाव में बड़ी कामयाबी के लिए बहुसंख्यक सांप्रदायिकता तथा जातिवाद के मेल समेत सभी तिकड़में ही नहीं आगवाई थी, सीपीएम का प्रमुख सामाजिक आधार माने जाने वाले निम्नलि जाति के एड़ना समुदाय में संचल लाने की उम्मीद में एसएनडीपी योगम से जुड़े

चलते चलते

अतिथि देवो भवः

मेहमान का निरादर करने की मनाही दी। गलती से निरादर हो जाने में भी संस्कृति से लेकर अर्थव्यवस्था तक को क्षति पहुँचाने का दोषी मान लिए जाने का दावा है। उसने जब दसवीं बार कहा ताजमहल, तो मैंने ग्यारहवाँ विकल्प सुझा-मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर। वह बोला-अब भी, ग्यारहवीं जगह भी ताजमहल नहीं। मुझे कहना पड़-कभी नहीं, सीवी जगह भी जहाँ मेहमान का गुरु रक्षाभा-ताजमहल है वहाँ नहीं।

ताजमहल ही नहीं देना। मैंने दलौती दी-घार की निशानी पर ही बच कर अटके रहे। जैसे, प्यार की निशानी द्वारकाधीश का मंदिर भी है, राधा-कृष्ण के प्यार की निशानी। उसने बोला का रास्ता निकालने की कोशिश की-दोनों बच्चों न देना। तब तो सारसर बोलिं थी। मैंने विद्वकर कहा-सिक्क-वही पटकना है, या भारत को जानना भी है? भारत

मुद्रा

सर्व शिक्षा मिशन

एन्युअल स्टेट्स ऑफ़ एजुकेशन द्वारा 2016 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 11 से 14 वर्ष की उम्र के 3.5 प्रतिशत और 15 से 16 के बीच की आयु के 13.5 प्रतिशत बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। प्राथमिक स्तर पर यह प्रतिशत 2012-13 में 5.6 था। यूनेस्को के इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग को एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में हर साल उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 4.70 करोड़ बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। ऐसा किस कारण से होता है? समाजशास्त्रियों का कहना है कि बच्चों द्वारा शिक्षा अधूरी छोड़ देने के अनेक कारण हैं। कई बार सवाल उठता है कि सरकार के सर्व शिक्षा अभियान जैसे पहलूडी प्रयास कहीं चूहिया नतीजे तो नहीं दे रहे? लेकिन स्कूल बच्चे बनकर उसके पर जाते हैं। लोकप्रिय कॉमिक बुक होली के नाम पर छल सात पहर शुरू किया गया शक्तिमान सर्व शिक्षा अभियान या जैसा कि हमें आज भी याद है- सर्व शिक्षा मिशन के नाम से जाना जाता है, राज्य शासन और सेव द विद्वत नवक आश्रमकीय संगठन का सहयोगात्मक प्रयास है। इसमें शिक्षण शासन के सहीगणन प्रमुख भी शामिल हैं। अगस्त 2016 में 19 नर्रर और 183 बच्चों को, जो 14 जगहों बसियों में संकिए हैं। अधिकतर स्कूल छोड़ चुके थे बच्चे बाल अधिकारों में प्रतिक्षित हैं। उनके ससस, राजा बाजार, किटपुर और साइडसिटी के



राजनीतिक संगठन भारत धर्म जागरण सेना के साथ गजोड़ी भी किया था। लेकिन इस चुनाव में भी भाजपा को केरल विधान सभा में पहली बार प्रवेश देने के अलावा ज़्यादा सफलता नहीं मिली। उम्मीद के अनुसार कामयाबी नहीं मिलने के आरएसएस-भाजपा की हताशा ने हो केरल में राजनीतिक हिंसा के मौजूदा चक्र को शुरूआत कराई है। यह शुरुआत ईई मुख्यमंत्रियों के चुनाव क्षेत्र विनरयो में चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद निरंतर रहे विमल जुलुस पर आरएसएस के हमले से। इस घटना में सीपीएम कार्यकर्ता विद्रोहनाथ की मौत हुई। उसके बाद से चले हिंसा और प्रतिहिंसा के चक्र में अब तक आरएसएस के हमलों में सीपीएम के 13 कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है, और 250 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। आरएसएस के लोगों ने सीपीएम और उसके जसंगठनों के 60 कार्यालयों पर और 165 पार्टी कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले किए हैं। लेकिन याद रहे कि भाजपा-आरएसएस की मुहिम सिर्फ “लाल आतंक” के खिलाफ नहीं है। इसमें लाल के साथ बिस तरह “जेहादी” की जोड़ी दिया गया है, वह महत्वपूर्ण है। देश की सत्ताधारी पार्टी का जेहाद के साथ कम्युनिस्टों का संबंध जोड़ना सिर्फ निराधार हो नहीं है, सारसर गैर-विजयीदराना भी है। लेकिन, अपने खिलाफालाल आतंक का शोर मचाकर और कम्युनिस्टों को आक्रान्त विद्रोहनाथ से श्रेष्ठ देश में वामपंथ के प्रभाव को कुछ फीका करने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन केरल की जनता तो उनके “निंदारे हिंसा के शिकार” के स्वर्ग से भागीवत होने से रही। इसीलिए लाल के साथ “जेहादी” जोड़ दिया गया है, ताकि बहुसंख्यक सांप्रदायिकता की अपनी

संरकार और भाजपा के राजनीतिक विरोध की आवाज बनने से रोकने के लिए वामपंथ को कमजोर करने की कोशिश करना खास तौर पर जरूरी है। अब, जब ज़्यादातर विपक्षी पार्टियों को या तो सत्ता पक्ष द्वारा साधा जा चुका है, या सीबीआई केसों समेत तरह-तरह के मामलों में उलझाया जा चुका है, उन्हें वामपंथ से ही खास खतरा है, जिसकी आवाज राजनीतिक-वैचारिक रूप से प्रखर भी है, और आम जनता के बीच उसकी अनुगुं भी है। इसीलिए आरएसएस-भाजपा के यह हमला है। पर क्या टाट के परदे से आधियों कर सकती हैं?

अर्थव्यवस्था की सेहत का सवाल

आभा ख्यामी पूरे देश में दैवस को एक पणाली के रूप में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू करते समय यह आशंका व्यक्त की गई थी कि इसके चलते अर्थव्यवस्था में कुछ समय के लिए उछाहक की स्थिति देखने को मिल सकती है। बर्तमान में ऐसा ही दिख रहा है। पिछली राजनीति में विकास दर जिस तरह 5.7 प्रतिशत हो दर्न की गई, उससे ताम्ना। राजनेता और कुछ अर्थशास्त्री यह कहने लगे कि अर्थव्यवस्था के हालात ठीक नहीं हैं। उनीना वित्त के कुछ उर्जित आंकड़े भी सकेते हैं, लेकिन महत्व एक तथ्यावली के विकास दर में गिरावट के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि देश की अर्थव्यवस्था सतलत में जा रही है और आर्थिक सुस्ती ने स्वायी रूप ले लिया है। गौरतलब है कि तेज विकास के लक्षित से सत्ता प्रतिशत की दर को ठीक-उक माना जाता है और भारत पिछले दो-तीन वर्षों में औसतन ऐसा रफार से प्राप्ति कर रहा है। इसकी भी अनेकही नहीं कर सकते कि विकास दर में गिरावट से केंद्र सरकार के नीति-निर्णया चिंतित हैं और उनकी ओर से ऐसे काम उठाए जा रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को फिर से पट्टी पर लाया जा सके। अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रभाव कोई नई-अनोखी बात नहीं, क्योंकि जिन भी देशों में जीएसटी जैसी व्यवस्था लागू की गई, उनमें शुरुआती कुछ महीनों में मंदी जैसा हालात सामने आए, और फिर बाद में अर्थव्यवस्था को कोई स्तर पर फायदा हुआ। स्पष्ट है कि यह उम्मीद अनुचित नहीं कि चंद महीनों बाद जब जीएसटी व्यवस्था ठीक तरीके से लागू हो जाएगी और उद्योग-व्यापार जगमग इसे भलीभांति समझ लेगा, तो आर्थिक तस्वीर में बुनियादी बदलाव देखने को मिलेगा। किसी भी सरकार के कामकाज का एक महत्वपूर्ण पैमाना अर्थव्यवस्था की हालत होती है। अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी भी गिरावट के संकेत दिखते ही लोग सरकार के कामकाज में मौनमूक निरालेन लगते हैं और ताम्ना तथ्य के सुझाव दिए जाने लगते हैं। इसके साथ ही राजनेता और अर्थशास्त्री अपने-अपने हिसाब से विश्लेषण करने लगते हैं।

इस संकट की चर्चा मीडिया में होने लगती है और इस तरह जनता भी अधिक हालात के प्रति सजग हो जाती है। अर्थव्यवस्था में गिरावट दिखने को सरकार की बखीब उछाहक का मौका देती है। इन दिनों वह इसी मौके का लाभ उठा रही है। इसी क्रम में वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने भी एक लेख लिखकर आर्थिक हालात को डबाने तस्वीर खींच दी। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्हें आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने का अधिकार है, लेकिन दुर्भाग्य से उनका द्वारा मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ अपना प्रभास निकालना अधिकार है।

उनके लेख में तो आर्थिक हालात की बेहतरी का कोई सुझाव था और न ही मौजूदा स्थिति की कोई तर्कपूर्ण समीक्षा। देश की आर्थिक स्थिति पर यशवंत सिन्हा का आकलन मोदी सरकार के लिए राजनीतिक तौर पर गले हो एक मसला बन गया हो, लेकिन इसकी अनेकही नहीं की जा सकती कि अर्थव्यवस्था की शहत एक या दो सेक्टरों से तन नहीं होती। अर्थव्यवस्था के ताम्ना आधार होते हैं। उनमें समय-समय पर उदार-चुदावी भी दिखावा रहता है। लगता है कि यशवंत सिन्हा ने यह सब देखने-समझने से इस्तीफा इनकार किया, क्योंकि वह जेटली की कोशना चाह रहे हैं। जाहिर है कि इसके जवाब में जेटली ने भी तीखे शब्दों का इस्तेमाल करके हुए यशवंत सिन्हा को अस्सी साल में रोजगार दूँद रहे व्यक्ति की संज्ञा दी।

प्रवेश पर और सर्टीफिकेट पर अपलोड
लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को ई-प्रवेश पर तय केंद्रों की सूची में शर्मिस्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अभ्यर्थी प्रवेश पर डाउनलोड करने के बाद गैल नंबर के आधार पर परीक्षा केंद्र का मिलान केंद्रों की सूची से करेंगे।

11 लाख अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन
बिहार पुलिस में सिपाही के लिए 9900 पदों पर बहाली होनी है। इसके लिए पुलिस में 11 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पुलिस के 9900 पदों पर बहाली के लिए 31 जुलाई से 30 अगस्त तक आवेदन लिए जाये गे।



वडनगर में मोदी, 40 कटआऊट पोस्टर में पीएम का जीवन-चरित्र

के साथ नृत्य किया जाएगा। गढ़वी और उनके साथियों द्वारा वडनगर से वाराणसी तक की गाथा गाई जाएगी।

सड़क हादसे में एक ही परिवार
के तीन की मौत, नौ घायल

चायलों को अस्पताल पहुँचाया। पुलिसने मामला दर्ज कर जांच शुरु की है। वहीं एक ओर घटना में सुत सेन्ट्रल जेल के सुबेदार हर्षदभाई तंबोली अपने परिवार के साथ बहुचर्चाई मंदिर दर्शन के लिए एला रहे थे। मेहसना हाईवे पर शिवाला साँखे पर हर्षदभाई को कार को ट्रेकर ने अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में सुबेदार हर्षदभाई की मौत पर ही मौत हो गई। जबकि चार महिलाएँ जख्मी हो गईं।

जिस केबिन पर चाय बेची थी, उस केबिन को विशेष रूप से सजाया गया है। केबिन के आगे रेल्वे के पुराने जमाने की बेंच भी रखी गई हैं। इसके अलावा केतली की प्रतिकृति भी रखी गई है। पर रेल्वे स्टेशन परिसर को फलों से सजाया गया है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा 4 ओ-ब्लॉक आगम नवकार कॉम्प्लेक्स सबीन रेल्वे स्टेशन के पास, सूरत, जि. सूरत, गुजरात से प्रकाशित, एवं तामीलोक पब्लिकेशन 152, 153 श्री गम इंडस्ट्रीयल एरिया पांडेसरा सूरत 394210 से मुद्रत. फोन नं. 9879141480 संपादक सुरेश मौर्या (पी आर बी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी) E-mail: krantisamav@gmail.com